

राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफआर-एआरआरसी/ 322

दिनांक: 24 मई, 2006

परिपत्र

(एफआर-एआरआरसी सं. 131)

विषय :- राज्य सरकार के विभागों की बकाया राशि का भुगतान ।

निगम द्वारा दिनांक 26.7.02 को जारी परिपत्र संख्या एआरआरसी-50 द्वारा विक्रय की गई इकाइयों से प्राप्त विक्रय राशि में से 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को देय राशि हेतु अलग से निर्धारित किया जाता है । विभिन्न शाखाओं से इस सम्बन्ध में उपरोक्त नीति निर्धारित होने से पूर्व विक्रय की गई इकाइयों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु संदर्भ प्राप्त हुए हैं । जो इकाइयाँ निगम द्वारा उपरोक्त नीति जारी होने के बाद निगम की देय राशि नहीं चुकाने के पत्रस्वरूप पुनः अधिमृहीत कर ली गई है एवं उसे पुनः विक्रय कर दिया गया है, जो शाखा कार्यालयों द्वारा बार-बार यह संदर्भ भेजा जा रहा है कि क्या पूर्व में बेची गई इकाई से संबंधित राज्य सरकार के विभागों की बकाया राशि का भुगतान निगम को करना पड़ेगा । इस संदर्भ में विषय की आवश्यक जांच कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

1. निगम द्वारा दिनांक 26.7.02 को जारी किए गए परिपत्र के बाद विक्रय की समस्त इकाइयों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की बकाया राशि चाहे वो इस परिपत्र के जारी होने से पहले को हो एवं जिसे पूर्व केंद्र द्वारा वहन करने का दायित्व हो एवं नहीं चुकाया गया है, का भुगतान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को नियमानुसार करेगा ।

- 7 नियम द्वारा चकाई गई राशि को पूर्व के केला के खाते में (जिसने अपरिणत नियम जारी होने से पूर्व इकाई को खरीदा था) में डेबिट किया जावेगा एवं शेष अधिदेय राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

~~अतः इस संकल्प में सभी संबन्धित प्रकरणों में शाखा कार्यालय अपने स्तर पर आवश्यक निर्णय लेकर लम्बित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें ।~~


(करण सिंह रावत)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यालय में मानक परिचालन
2. समस्त उप महाप्रबन्धक (क्षेत्रीय), समस्त शाखा/उप शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर